

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 107/2023

(अपील संख्या – 1854/2022)

गौरव सिंह

—प्रार्थी—अपीलार्थी

बनाम

1. श्री टी. रविकांत, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री जोगाराम, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
3. श्री अवधेश सिंह, संयुक्त शासन सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग (ग्रुप-3), शासन सचिवालय, जयपुर।

—अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.08.2023

आदेश की दिनांक : 16.07.2024

उपस्थित :-

प्रार्थी—अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

अप्रार्थी—प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से : श्री सोमेश चन्द शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी—अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 1854/2022 में दिनांक 03.07.2023 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 03.07.2023 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :-

“प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति आदेश दिनांक 06.04.2011 के द्वारा

कनिष्ठ अभियंता के पद पर जयपुर विकास प्राधिकरण में हुई थी। अनुलग्नक-2 दिनांक 10.02.2010 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि नगरीय विकास विभाग द्वारा कुल 167 कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों की विज्ञापित जारी की गई, जिसके क्रम में आदेश दिनांक 06.04.2011 (अनुलग्नक-3) के द्वारा 69 कार्मिकों को उनके नामों के आगे चिह्नित संस्थानों में नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 54 पर अंकित है, जिसमें अपीलार्थी को जयपुर विकास प्राधिकरण में नियुक्ति दी गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण का कार्मिक है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी जानकारी अनुलग्नक-9 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि सहायक अभियंता के पद 62 एवं कनिष्ठ अभियंता के पद 139 हैं। जहां तक वरिष्ठता सूची दिनांक 21.10.2021 (अनुलग्नक-6) जो नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी किए जाने का प्रश्न है, उक्त वरिष्ठता सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 229 पर अंकित किया गया है। जबकि उक्त सूची में न तो प्राधिकरण का नाम अंकित किया गया और न ही अन्य संस्थानों के नाम अंकित किए गए हैं। उक्त सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौनसा व्यक्ति किस संस्थान का कार्मिक है। जबकि नियुक्ति आदेश में कार्मिक की नियुक्ति एवं आवंटित संस्थान का नाम अंकित किया गया है। नगरीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न संस्थानों की सम्मिलित वरिष्ठता सूची जारी की गई है जबकि नियुक्ति आदेशों में कार्मिकों को अलग-अलग संस्थानों में नियुक्ति दी गई है। नगरीय विकास विभाग द्वारा सभी संस्थानों की एक साथ सम्मिलित वरिष्ठता सूची जारी किए जाने से भिन्न-भिन्न संस्थानों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हमारे मत में नियुक्ति पत्र में उल्लेखित संस्थानों के आधार पर ही पृथक-पृथक संस्थान की पृथक-पृथक वरिष्ठता सूची जारी की जानी चाहिए और तदनुसार ही संस्थान में नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति उपलब्ध पदों के आधार पर ही की जानी चाहिए, जिससे संस्थान में कार्यरत कार्मिकों की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव न पड़े। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं की सम्मिलित वरिष्ठता सूची जारी किए जाने से जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत अपीलार्थी की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 01.04.2022 अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रथम नियुक्ति दिनांक में आवंटित संस्थानों के आधार पर कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी की जावे एवं तदनुसार निर्धारित वरिष्ठतानुसार रिव्यू डीपीसी आयोजित कर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जावे।”

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 03.07.2023 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। प्रत्यर्थी विभाग जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर

रहा है। इसलिए माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 03.07.2023 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

3. अप्रार्थी-प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया कि उत्तरदाता विपक्षी के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई अवमानना कारित नहीं की गयी है। माननीय अधिकरण के आदेशों की पालना में विपक्षी ने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कोताई नहीं की है। अतः जवाब अवमानना प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी-अपीलार्थी की अवमानना याचिका को निरस्त फरमावे।
4. हमने उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी-अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व अप्रार्थी-प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों की पुनरावृत्ति की।
5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :-

“प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति आदेश दिनांक 06.04.2011 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर जयपुर विकास प्राधिकरण में हुई थी। अनुलग्नक-2 दिनांक 10.02.2010 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि नगरीय विकास विभाग द्वारा कुल 167 कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके क्रम में आदेश दिनांक 06.04.2011 (अनुलग्नक-3) के द्वारा 69 कार्मिकों को उनके नामों के आगे चिह्नित संस्थानों में नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 54 पर अंकित है, जिसमें अपीलार्थी को जयपुर विकास प्राधिकरण में नियुक्ति दी गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण का कार्मिक है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी जानकारी अनुलग्नक-9 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि सहायक अभियंता के पद 62 एवं कनिष्ठ अभियंता के पद 139 हैं। जहां तक वरिष्ठता सूची दिनांक 21.10.2021 (अनुलग्नक-6) जो नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी किए जाने का प्रश्न है, उक्त वरिष्ठता सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 229 पर अंकित किया गया है। जबकि उक्त सूची में न तो प्राधिकरण का नाम अंकित किया गया और न ही अन्य संस्थानों के नाम अंकित किए गए हैं। उक्त सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा

रहा है कि कौनसा व्यक्ति किस संस्थान का कार्मिक है। जबकि नियुक्ति आदेश में कार्मिक की नियुक्ति एवं आवंटित संस्थान का नाम अंकित किया गया है। नगरीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न संस्थानों की सम्मिलित वरिष्ठता सूची जारी की गई है जबकि नियुक्ति आदेशों में कार्मिकों को अलग-अलग संस्थानों में नियुक्ति दी गई है। नगरीय विकास विभाग द्वारा सभी संस्थानों की एक साथ सम्मिलित वरिष्ठता सूची जारी किए जाने से भिन्न-भिन्न संस्थानों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हमारे मत में नियुक्ति पत्र में उल्लेखित संस्थानों के आधार पर ही पृथक-पृथक संस्थान की पृथक-पृथक वरिष्ठता सूची जारी की जानी चाहिए और तदनुसार ही संस्थान में नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति उपलब्ध पदों के आधार पर ही की जानी चाहिए, जिससे संस्थान में कार्यरत कार्मिकों की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव न पड़े। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं की सम्मिलित वरिष्ठता सूची जारी किए जाने से जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत अपीलार्थी की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 01.04.2022 अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रथम नियुक्ति दिनांक में आवंटित संस्थानों के आधार पर कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी की जावे एवं तदनुसार निर्धारित वरिष्ठतानुसार रिव्यू डीपीसी आयोजित कर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जावे।”

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी-अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिस्थीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :-

"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86) में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :-

"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :-

"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 03.07.2023 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए

अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी-अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य